दी गई सहायता का स्वरूप	वर्ष-वार राशि		
	1989-90	1990-91	1991-92
निम्नलिखित को ऋण:			
4. सामाजिक आवास योजनाओं के लिए राज्य सरकारों को	1056.00	1034.00	1101.00
5. शीर्ष सहकारी आवास, वित्त समितियां, आवास बोर्ड एवं अन्य प्राधिकरण	600.00	600.00	750.00
6. राज्य बिजली बोर्ड	6796.00	8130.00	—
7. राज्य सड़क परिवहन निगम	707.00	707.00	777.00
निगमित क्षेत्र			
8. शेयर, ऋणपत्र और कम्पनियों (सार्वजनिक,सहकारी और निजी क्षेत्र को ऋण)	1995.98	1419.83	4091.78
कुल:	14386.35	15890.83	12349.78

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की उत्तर प्रदेश में ग्रामीण रोजगार के संबंध में योजना

163. **चौधरी हरमोहन सिंह:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने व्यापक पैमाने पर ग्रामीण उद्योग शुरू करने में ग्रामीण लोगों की सहायता करने के लिए एक परियोजना तैयार की है जिससे उत्तर प्रदेश में रोजगार के अवसर पैदा करने में सहायता मिलेगी;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपर्युक्त बैंक की निकट भविष्य में उत्तर प्रदेश में कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) और (ख) चूंकि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) एक अखिल भारतीय संस्थान है, इसकी योजनाओं को किसी राज्य विशेष के संदर्भ में तैयार नहीं किया जाता है। बहरहाल, पुनर्वित्त की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सिडबी द्वारा प्रदान की गई सहायता से सम्पूर्ण देश में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन हुआ है। उत्तर प्रदेश में लघु उद्योगों ने भी सिडबी की विभिन्न योजनाओं के तहत सहायता का महत्वपूर्ण भार प्राप्त किया है और इसने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों के सृजन में भी सहायता की है।

विभिन्न राज्य स्तरीय संस्थाओं और वाणिज्यिक बैंकों को पुनर्वित्त सहायता प्रदान करने के अलावा, सिडबी, विभिन्न राज्यों में विकास संबंधी कार्य-कलापों को भी करता है। गत दो वर्षों के दौरान, सिडबी ने उत्तर प्रदेश में अलीगढ़, फैजाबाद, मुरादाबाद और गोरखपुर जैसे पारम्परिक केन्द्रों में चुने हुए औद्योगिक समूहों की प्रोद्योगिकी अभिवृद्धि, लघु उद्योग एककों के लिए कारबार सहायकों के प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम, विद्यमान उद्यमियों के प्रशिक्षण और ग्रामीण चमड़ा उद्योग परियोजनाओं की अभिवृद्धि के कुछ विकास संबंधी क्रियाकलापों को हाथ में लिया है।

(ग) सिडबी अपनी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राज्य में लघु उद्योग क्षेत्र में एककों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि करने का प्रयत्न करेगा।

Repayment of Foreign Loan

164. SHRI ASHIS SEN: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) what is the total amount required for repayment of principal and payment of interest on old loans taken by the country; and

(b) whether total receipt of fresh loans are sufficient to meet the repayment responsibilities?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI RAMESHWAR THAKUR): (a) The repayment of principal and payment of interest during 1992-93 on the outstanding foreign loans are estimated to be Rs. 9946 crores and Rs. 7763 crores respectively.

(b) The foreign loans are being repaid out of the country's foreign exchange inflows including export proceeds and invisible earnings, according to terms and conditions of each loan.

कच्छ जिले में पाकिस्तानी मुद्रा का प्रयोग किया जाना

165. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गुजरात के कच्छ जिले के अधिकांश भागों में पाकिस्तानी मुद्रा अधिक प्रचलित है और उसका रोजमर्रा के लेन-देन में प्रयोग किया जाता है;

(ख) क्या यह भी सच है राज्य सरकार ने इस बारे में केन्द्रीय सरकार को सूचित कर दिया है;

(ग) सरकार कच्छ जिले में इस राष्ट्र विरोधी गतिविधि को रोकने के लिये क्या कदम उठाने का विचार रखती है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश्वर ठाकुर): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

Investments with Canfina

166. SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) what is the total amount of investments made by the Central Public Sector Undertakings and Autonomous bodies with Canfina as on the 30th June, 1992, 31st July, 1992 and 31st August, 1992;

(b) what are the details of investments that have already matured and how many have been honoured by Canfina;

(c) whether it is a fact that Canfina's net worth has been wipted off due to losses suffered by its in Stock-Scam; and

(d) what steps Government propose to take to ensure that Canfina honours its commitments?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI DALBIR SINGH): (a) Canara Bank has reported that the total amount of investment made by Central Public Sector Undertakings and autonomous bodies with CANFINA in the form of Portfolio Management Services (PMS), Corporate Investment Advisory Services (CIAS) and Inter Corporate Deposits (ICD) on the relevant dates were as under:

30.6.92 — Rs. 2239.87 crores

31.7.92 — Rs. 2139.61 crores

31.8.92 — Rs. 2062.81 crores

(b) Out of the total investment of Rs. 2062.81 crores as on 31.8.92, Rs. 540.07 crores had matured on this date. Canfina has already honoured payments due totalling Rs. 201.64 crores after 31.8.92 till date.,

(c) and (d) CANFINA's net worth as on 31.3.92 stood at Rs. 86.81 crores. CANFINA has filed suit against Bank of Karad and also lodged criminal complaints against brokers and others for recovery of its dues before the Special Court and the CBI respectively. As these cases are still pending, CANFINA net worth cannot be precisely determined at this stage. CANFINA has requested for rescheduling of the dues of concerned Public Sector Undertakings and are working out the modalities in consultation with the Public Sector Undertakings. With the assets in its possession and sale of securities at the appropriate time, CANFINA is hopeful of meeting it obligations.

Spurt in Smuggling on Indo-Pak Border

167. SHRI IQBAL SINGH: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether there has been a spurt in smuggling on the Indo-Pak border in the recent past;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) what is the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE